from 28.1.1995 to 20.11.1996, using cheque leaves from the cheque book which was not handed over to the account holder.

(c) The matter has been investigated by the Zonal Office, Bank of India as well as by the Police. The employees of the St. John Ambulance Brigade who had collected the cheque books and withdrawn money by forging signature has been dismissed from the services by his employer. The question of staff accountability will arise in the event of the result of police investigation pointing in that direction.

(d) As and when a fraud comes to the notice in public sector banks, the matter is investigated by the concerned authorities and at the time of investigation staff accountability is also looked into.

बैंक-ऋणों के चूककर्ता

661. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा यह मांग की गई है कि बैंकों से 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेने वाले ऋणी व्यक्तियों के नाम घोषित किए जाएं जो निर्धारित समय के भीतर ऋण चुकाने में विफल रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्धारित समय के भीतर ऋण वापस न कर पाने वाले ऋणी व्यक्तियों के ऊपर 42,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अनुमानतः ऐसी कितनी बकाया राशि है; और

(घ) सरकार ऐसे चूककर्ताओं के नामों की सूची कब तक प्रकाशित कर देगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव ने दिनांक 19 दिसम्बर, 1996 को तत्कालीन वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें बैंकिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 लाख रुपए से अधिक के सभी बैंक चूककर्ताओं की सूची का पूर्ण रूप से प्रकटन शामिल था।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उनके पास अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर दिनांक 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 43577.89 करोड़ रुपए की राशि अनुपयोज्य आस्थियों (एन०पी०ए०) के रूप में बकाया है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय III-क में निहित उपबंधों के अनुसार व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के ब्यौरे प्रकट करना मना है। जब किसी उधारकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाता है, ये ब्यौरे प्रकट किए जा सकते हैं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को उन उधार खातों की सूची प्रकाशित करता है जिनकी कुल राशि एक करोड़ रुपए और उससे अधिक है तथा जिनके विरुद्ध बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने अपनी प्राप्त राशियों की वसूली के लिए वाद दायर किए हैं।

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

662. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कुल अवमूल्यन का प्रतिशत क्या था; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान अवमूल्यन के कारण देश को विदेशी ऋण के भुगतान के संबंध में ब्याज और ऋण की किस्त के रूप में कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा और मार्च, 1997 और मार्च, 1998 के अन्त में विदेशी ऋण की राशि कितनी-कितनी थी?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) और (ख) भारत में रुपए की विनिमय दर बाजार निर्धारित होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, रुपए की विनिमय दर दैनिक आधार पर दोनों दिशाओं में परिवर्तित होती रहती है। 1997-98 के दौरान, अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में 1996-97 के औसत मूल्य की तुलना में 4.48 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ।

(ग) विदेशी ऋण पर ऋण सेवा अदायगियां (ऋण की वापसी अदायगियां और ब्याज अदायगियां) साधारणतया उस मुद्रा में की जाती हैं जिसमें ऋण मूल्यवर्गित होता है। इस प्रकार रुपए की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव संबंधित मुद्राओं में देश की विदेशी ऋण

सेवा देयताओं की मात्रा को प्रभावित नहीं करते। परन्तु, रुपए के अर्थों में, ऋण सेवा अदायगियों में रुपए के अवमूल्यन या वृद्धि के अनुसार ही वृद्धि या कमी होती है। मार्च, 1997 के अन्त में और सितम्बर, 1997 के अन्त में (वह अद्यतन तारीख जिसके लिए सूचना उपलब्ध है) विदेशी ऋण की धनराशियां निम्नानुसार हैं:—

	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डॉलर
मार्च, 1997 के अन्त में	331355	92224
सितम्बर, 1997 के अन्त में	336646	92883

विभिन्न क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश

663. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां देश में संचार, इस्पात, तैल शोधन और विद्युत क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वे कौन-कौन से औद्योगिक घराने हैं जिन्होंने अब तक ऐसी कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौते (करार) करने का प्रयास किया है,

(ग) क्या सरकार ने उनके निवेश संबंधी प्रस्तावों में अपनी रुचि दर्शायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

Steps taken to Boost Economy

664. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the steps Government have taken to contain sluggishness of the economy, during the last six months;

(b) whether Government propose to depreciate the Rupee; and

(c) if not, steps taken by R.B.I. to arrest forces which could lead to depreciation of Rupee?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Major policies taken by the Government during the last six months include Export Import Policy, 1997-2002 revised on April 13, 1998 which has further expanded the list of Open General Licence (OGL) items by shifting 340 items from the restricted category to the OGL; monetary and credit policy measures for the first half of 1998-99 leading to reduction in bank rate to 9 per cent and ensuring credit availability commensurate with the growth potential and; supply side measures relating to industrial and investment policies and facilitating private investment in infrastructure and easing infrastructure constraints.

(b) and (c) The exchange rate of the Rupee is market determined. The exchange rate developments are monitored on a day to day basis by the Reserve Bank of India (RBI), and measures are taken as and when necessary, to maintain orderly market conditions. RBI has ensured orderly conditions in the market.

Panel on Issue of Converting Rupee Debt into Hard Currency Loan

665. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have set up a two member inter counting panel to look into the issue of converting India's outstanding rupee debt into hard currency loan and if so, whether it has submitted its report to Government;

(b) if so, furnish details thereof;

(c) details regarding present status of decision taken; and

(d) whether Government have received